Statement

Funds allocated under IAY during 1995-96

(Rs. in Lakhs)

s. No.	State/U.T.	Allocation Central
1.	2.	3.
1.	Andhra Pradesh	7764.21
2.	Arunachal Pradesh	79.71
3.	Assam	2555.95
4.	Bihar	15229.21
5.	Goa	86.12
6.	Gujarat	2850.09
7.	Haryana	684.63
8.	Himachal Pradesh	556.07
9.	Karnataka	5213.33
10.	J & K	556.07
11.	Kerala	1896.68
12.	M.P.	9838.39
13.	Maharashtra	8464.06
14.	Manipur	102.16
15.	Mcghalaya	119.54
16.	Mizoram	50.36
17.	Nagaland	128.13
18.	Orissa	6298.60
19.	Punjab	486.85
20.	Rajasthan	4087.49
21.	Sikkim	46.65
22.	T.N.	7018.73
23.	Tripura	132.69
24.	U.P.	18921.14
25.	W.B.	6957.87
26.	A & N Islands	47.17
27.	D & N Haveli	25.61
28.	Daman & Diu	15.08
29.	Lakshadweep	23.65
30.	Pondicherry	46.18
	TOTAL :	100000.00

नार्थ/ साऊथ एवेन्यूए स्थित गैराजों में अवैध व्यापार

1142. श्री गोविन्द राम मिरी : क्या शहरी का और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क)क्या नार्थ एवेन्यू और साउथ एवेन्यू सरकारी गैराजों में और खुले भू-क्षेत्र पर अवैध कारोबार/होटल और अन्य व्यावसायिक केन्द्र अभी चल रहे हैं;

(ख)यदि हां, तो इसे रोकने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार हैं;

(ग)क्या नई दिल्ली नगर परिषद ने इस अवैध केन्द्रों को कोई कानूनी समन जारी किया हैं;

(घ)क्या ऐसेअवैध कारोबार से सांसदों की सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह लग गया हैं; और

(ड.)यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया हैं?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में शहरी विकास विभाग के राज्य मंत्री (श्री आर0 के0 धवन) : (क) से (ड.) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग बताया हैं कि नॉर्थ तथा साऊथ एवेन्यू में खंले क्षेत्रों कोई अतिक्रमण नहीं हैं। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग यह भी बताया है कि नॉर्थ/साऊथ एवेन्यू में 21 गैर का इस्तेमाल होटल, टेण्ट हाऊस तथा दुकानों वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए किया जा रहा हैं। घटनाओं की सुचना केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा समय-समय पर लोक सभा तथा राज्य सभा सचिवालय को दी जाती हैं क्योंकि इन मकानों और गैराजों आबंटन सम्बन्धित सदन की समितियों द्वारा किया जा रहा हैं।ण अवैध इस्तेमाल पर अंकुश लगाने के लिए लोक सभा तथा राज्य सभा सचिवालयों द्वारा की गई ज्ञात नहीं हैं।

Rehabilitation Package fur PSUs

1143. SHRI B.K. HAR1PRASA Will the MINISTER OF INDUSTRY pleased to state:

(a) whether it is a fact that many making PSUs, which have been refend to BIFR, arc still in a limbo due to dc in disposal of the cases by BIFR;

(b) whether Government would consider ploughing back the procect under the disinvestment schemes in pr making PSUs, to the revival of the